

The Gazette of India

TINDHTUA YE CEHZILEV

सं 22]

नई विल्ली, शनिवार, जून 2, 1973 (ज्येष्ट 12, 1895)

No. 22]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 2, 1973 (JYAISTHA 12, 1895)

इस भाग में भिन्न पूष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस (NOTICE)

नीव लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 2 फरवरी 1973 तक प्रकाशित किये गये हैं :--

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 2nd Pebruary 1973:-

र्जंक संख्या और तिथि द्वारा जारी किया गया विषय Issue No. and Date Issued by Subject

> -मृत्य-- Nii-

ऊपर लिखे असाधारण राजपतों की प्रतिया नियंत्रक प्रकाशन, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्न भेजने पर भेज दी आएंगी । मांग-पत्न नियंत्रक के पास इन राजपतों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए।

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi, Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these Gazettes.

81GI/73

		-		_		
		बिषय-सूर	मा	782		
	- 1: (पुष्ठ	भाग 11खंड 3उपखंड (ii)(रक्षा मंता-	पृष्ठ		
माग	I—चंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर)		लय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों			
	भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम		और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को			
	म्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों,		ओड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारीं द्वारा विधि			
	विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से		छाङ्कर) कन्द्राय प्राप्तकारा द्वारा जाव के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए			
	सम्बन्धित अधिसूचनाएं	563	·	1041		
भाग	Iखंड 2(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर)		आदेश और अधिसूचनाएं	1941		
	भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम		भाग IIखंड 4रक्षा मंत्रालय द्वारा अधि-			
	न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी		सूचित विधिक नियम और आदेश	169		
	बफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों,		भाग IIIखंड 1महालेखा परीक्षक, संघ सोक-			
,	कुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	843	सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों			
भाग	I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की		और भारत सरकार के अधीन तथा संसन्त			
	गई विश्वितर नियमों, विनियमों, आवेशों		कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	947		
	और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	77	भाग 111खंड 2एकस्व कार्यालय, कलकता			
भाग	I— खंड 4 — रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की		द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	247		
	गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों,		भाग IIIखंड 3मृक्य आयुक्तों द्वारा या			
	छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	619	उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	27		
- धारत	IIवांड 1अधिनियम, अध्यादेश और	V = U	माग 111खंड 4 विधिक निकायों द्वारी जारी			
*11"	विनियम		की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधि-			
			सूचनाएं, आदेश, विज्ञापन भौर नोटिसें			
भाग	∐—-खंड 2विधेयक और विधेयकों संबंधी		शामिल हैं	1561		
	प्रवर समितियों की रिपोर्ट		भाग IVगैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-	-001		
	× · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन सथा नोटिसें	99		
भाग	IIखंड 3उपखंड (i)(रक्षा मंत्रालय			99		
	को छोड़कर) मारत सरकार के मंत्रा-		पूरक संख्या 22			
	लयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों		26 मई, 1973 की समाप्त होने नाले सप्ताइ			
	को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी		की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट .	687		
	किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और		5 मई, 1973 को समाप्त होने वाले सप्ताह			
	जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें		के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे			
	साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम		अधिक आवादी के शह्र्रों में जन्म तथा बड़ी			
	आदि सम्मिलित हैं)	1073	थीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंक <i>ड़े</i> .	703		
CONTENTS						
PART	I-Section 1Notifications relating to Non-	PAGE	PART II—SECTION 3.—SUBSEC. (ii).—Statutory	PAGE		
	Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the		Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India			
	Government of India (other than the		(other than the Ministry of Defence) and			
	Ministry of Defence) and by the Supreme	563	by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	1941		
PART	I—Section 2.—Notifications regarding Ap-		PART II SECTION 4.—Statutory Rules and Orders			
	pointments, Promotions Leave etc. of Government Officers issued by the Minis-		notified by the Ministry of Defence PART III—Section 1.—Notifications issued by the	169		
	tries of the Government of India (other		Auditor General, Union Public Service			
	than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	843	Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate			
PART	ISection 3Notifications relating to Non-	•	Offices of the Government of India PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices	947		
	Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of		issued by the Patent Offices Calcutta	247		
_	Defence	/7	PART III—Section 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commis-			
PART	ISection 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of		Sioners	27		
-	Officers issued by the Ministry of Defence.	619	PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertise-			
PART	II.—Section I.— Acts, Ordinances and Regulations		ments and Notices issued by Statutory Bodies	1 884		
PART	IISection 2Bills and Reports of Select		PART IV-Advertisements and Notices by Private	1561		
	Committees on Bills		Individuals and Private Bodies	99		
PART	II.—Section 3.—SUB.Sec. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws		Supplement No. 22 Weekly Epidemiological Reports for week ending			
	etc, of general character) issued by the		20th May, 1973	687		
	Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and			
	by Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories	1073	over in India during week ending 5th May, 1973	703		

भाग ।__ख•ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 मई 1973

सं० 34-प्रेज/73---राष्ट्रपति सहर्ष यह निदेश देते हैं कि दिनांक 22 फरवरी 1962 की अधिसूचना सं० 29-प्रेज/62 के अन्तर्गत दिनांक 3 मार्च 1962 के भारतीय राजपत्न के भाग 1 खण्ड 1 में प्रकाशित पुलिस (स्पेशल ड्यूटी) मैंडल सम्बन्धी संविधि में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :--

- (1) संविधि की प्रस्तावना में, "केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा केन्द्रीय खुफिया ब्यूरो सहित पुलिस दलों के सदस्य" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित करें:---
 - ''पुलिस दलों, केन्द्रीय पुलिस/सुरक्षा संगठनों के सदस्य ।''
- (2) तृतीयतः खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें:—यह मैंडल पुलिस दलों, केन्द्रीय पुलिस/सुरक्षा संगठनों के उन सदस्यों को दिया जाएगा जिन्होंने उन परिस्थितियों में तथा उन अविधयों में सेवा की ह्यो जो इस पुरस्कार के लिए समय-समय पर भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्य हों। ये पुरस्कार मरणोपरान्त भी दिए जा सकते हैं।
- (3) षष्टतः खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें:—जिन व्यक्तियों को यह मैंडल दिया जाय उनके नाम भारतीय राजपन्न में प्रकाशित किए जा सक्ते हैं तथा नामों का एक रजिस्टर गृह मन्त्रालय में उस व्यक्ति द्वारा रखा जाए जिसे राष्ट्रपति निदेश दें।

सं० 35-पेज/73--राष्ट्रपति सहर्ष यह निदेश देते हैं कि दिनांक 23 फरवरी 1962 की अधिसूचना सं० 30-प्रेज/62 के अन्तर्गत 3 मार्च, 1962 के भारतीय राजपत्न के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित पुलिस (स्वेशल इयूटी) मैंडल संबंधी नियमों में निम्न-लिखित संशोधन किया जाएगा:---

''नियम 2 विलोपित कर दिया जाय''

अशोक गित्र राष्ट्रपति के मचित्र

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 14 मई 1973

सं० 5/1/73/पी० ए० सी०—लोक सभा तथा राज्य सभा के निम्नलिखिन सदस्य लोक नेखा समिति के 30 अप्रैल, 1974 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित हुए हैं।

लोक सभा के सदस्य

- 1. श्री धर्मराव शरणप्पा अफजलपुरकर
- 2. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल
- श्री सत्य चरण बेसरा
- 4. श्री ज्योतिर्भय बस्
- 5. श्री एम० दीवीकन
- 6. श्रीसी० डी० गौतम
- 7. श्री वाई० एस० महाजन
- 8. श्री विभृति मिश्र
- 9 श्री एच० एन० मुकर्जी
- 10. श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली
- 11. श्री नारायण चन्द्र पाराशर
- 12. श्री एच० एस० पटेल
- 13. श्री पी० एंथनी रेड्डी
- 14. श्री विश्व नारायण शास्त्री
- 15 श्री सुन्दर लाल

राज्य सभा के सदस्य

- 16. श्री एम० आनन्दम्,
- 17. श्री गोलाप वरबोरा
- 18. श्री विपिनपाल दास
- 19. श्री नवल किशीर
- 20. श्री पी० एस० पाटिल
- 21. श्री शशांक शेखर सन्याल
- 22. श्री सवाई सिंह सिसोदिया
- अध्यक्ष महोदय ने धी ज्योतिर्मय बसु को समिति का सभापति नियुक्त किया है।

एम० एस० सुन्द्रसेन, उप-सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1973

सं० 3/1/ई० सी० एक/73—अध्यक्ष महोदय ने श्री कमल नाथ तिवारी को प्राक्कलन समिति के 30 अप्रैल, 1974 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए प्राक्कलन समिति का सभापति नियुक्त किया है।

जी० डी० शर्मा, उप-सचिव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) पत्रिका पक्ष

नई दिल्ली, दिनांक 16 मई 1973 संकल्प में संशोधन

सं० ई०-13016/3/72-प० (हि०वि०पु०)—विधि और न्याय मंत्रालय के संकल्प सं० 22/4/69-प० (प्रशा०), दिनांक 1 मार्च 1972, में, जो हिन्दी में मानक विधि पुस्तकों के लेखन, अनुवाद और प्रकाशन की स्कीम के प्रभावी कांयांन्वयन के लिए सलाह दूरेने के लिए मुल्यांकन समिति की संरचना के सम्बन्ध में है, क्रम संख्या 4 और उस क्रम संख्या के सामने की प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"4 श्री एस० एन० चतुर्वेदी, सदस्य, राज भाषा (विधायी) आयोग, नई दिल्ली ।

सदस्य''

नरेन्द्र कुमार सेठ, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 मई 1973 संकल्प

सं॰ \mathbf{x} ०-13011/2/73-हिन्दी-2—गृह मंत्रालय के 9 प्रगस्त, 1972 के संकल्प सं० 8/6/71-हिन्दी-2 के प्रधीन पुनर्गिठित हिन्दी सलाहकार समिति में श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रधान मंत्री के स्थान पर, भारत सरकार श्री उमाशंकर दीक्षित, गृह मंत्री को श्रध्यक्ष के रूप में सहर्ष नियुक्त करती है

आवेश

श्रादेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राष्ट्रपति के सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री के सचिवालय, योजना श्रायोग, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व का महालेखाकार, नई दिल्ली, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाएं।

यह भी प्रादेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्व-साधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्न में प्रकाशित किया जाए।

प्रेम नाथ धीर, उप-सचिव

नई दिल्ली 110001, दिनांक 16 मई 1973

सं० 26/12/72 ए० एन० एल०—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 4 अक्तूबर 1972 की अधिसूचना सं० 26/12/72—ए० एन० एल० के आशिक आशोधन में, राष्ट्रपति यह निदेश देते हैं कि उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 3 में निम्नलिखित उपबंध जोड़ दिया जायेगा:—

"यह व्यवस्था की जाती है कि इस अधिसूचना के अधीन गठित की गयी प्रथम सलाहकार समिति के लिये निर्वाचित इस प्रकार सदस्यों की सदस्यता की अवधि 31 मार्च, 1974 तक होगी"

जयाकर जानसन, उप-सचिव

वाणिज्य मंद्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 मई 1973

सं० 1(3)/73-ई० पी० जैंड—-राष्ट्रपति, श्री एस० राजगोपाल, आई० ए० एस० को 1 मई, 1973 के पूर्वाह्म से आगामी आवेश जारी होने तक के लिए विकास आयुक्त सांताकुज इलैक्ट्रानिक्स एक्सपोर्ट प्रासैसिंग जोन, बम्बई के रूप में नियुक्त करते हैं।

एन० एस० विद्यानाथन, उप-सचिव

इस्पात और खान मंत्रालय सार्वजनिक सुचना

विषय:—भारतीय मानकों को लागू करना इस्पात के लिये प्रमाण-चिन्ह योजना

नई विल्ली दिनांक मई 1973

सं० एस० सी०(1)-32(4)/72--इस मंत्रालय के दिनांक 4 जनवरी 1965 की सार्वजनिक सूचना संख्या एस० सी० (सी०)-2(44)/63-II के पैरा 2 तथा 10 का आंशिक आशोधन करते हुए तथा इस्पात के उत्पादों के उत्पादन में हुई प्रगति और बहुत सी विशिष्ठियों को भारतीय मानक संस्थान की गण-चिन्ह योजना के अन्तर्गत लाने की योजना के ऋमिक विस्तार तथा भारतीय मानक संस्थान की विशिष्ठियों को यथा समय कम करने की सरकार की मंशा को दृष्टिगत रखते हए अब यह निश्चय किया गया है कि भविष्य में बिना भारतीय मानक संस्थान की विशिष्ठियों के सब प्रकार के इस्पात के परीक्षण तथा प्रमाणन उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के आपसी समझौते द्वारा किये जायेग । फिर भी, यदि कोई उपभोक्ता किसी अन्य पक्षकार अर्थात उद्योग निदेशक (धातुकर्म) से परीक्षण प्रमाण पत्र जारी कराना चाहें तो प्राधिकृत अभि-करण/प्राधिकरण के रूप में उद्योग निदेशक (धातुकर्म) दवारा परीक्षण प्रमाण पत्र जारी किये जाते रहेगें। टी० घोष, लोहा तथा इस्पात नियंत्रक

विज्ञाम और औद्योगिक विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 29 मई 1973

कु० सं० डी॰ एस॰ टी॰/1(2)/73-प्रा० इ० स०—राष्ट्रपति सह्यं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ के सामान्य शिक्षा केन्द्र के प्राध्यापक व संग्रहालय अध्यक्ष श्री इपितखार आलम खान को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में संग्रहालय अध्यक्ष के अस्थाई पद पर ६० 700-40-1100-50/2-1250 के वेतन मान में दिनांक 7 मई, 1973 (पूर्वाह्र) से आगामी आदेश जारी करने तक के लिए नियुक्त करते हैं।

एम० आर० राजागोपालन, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 मई 1973

सं० 10-1/71-फेट-अधिसूचना सं० 10-2/71-फेट, दिनांक 16/20 अक्तूबर, 1971 के कम में, श्री मोहन सिंह, सदस्य विधान सभा, उत्तर प्रदेश ग्राम—तिलोई, जिला—रायबरेली, को अब तक संशोधित संकल्प संख्या 10-1/65-फेट, दिनांक 9 दिसतम्बर, 1966 के अन्तर्गत पुनर्गठित राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन सम्पर्क समिति में स्वर्गीय श्री राज नारायण मिश्र के स्थान पर ग्रामीण जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 3 वर्षी की अविध के लिए मनो-नीत किया जाता है।

पी० वी० शेनोई, निदेशक (विदेश सहायता)

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 मई 1973 संकल्प

विषय:---राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना

सं० एफ० 7-6/71-स्कूल-2-शिक्षा आयोग (1964-66) ने अध्यापकों को शिक्षा के स्तरों को बनाए रखने में भारत सरकार की भूमिका परिवचार-विमर्श किया था। आयोग ने, अध्यापकों की शिक्षा के सुधार के लिए प्रचुर निधियों की व्यवस्था करने की सिफारिश भी की थी। उसने यह भी सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालय अनुवान आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के सहयोग से एक संयुक्त अध्यापक शिक्षा स्थायी समिति स्थापित कर वी गई है।

- 2. िषक्षा आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों पर, अध्यापकों के लिए कम से कम दो वर्षीय, प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। आयोग का यह अभिमत था कि अध्यापक शिक्षा के विद्यमान कार्यक्रम अधिकांश रूप से परम्परागत, कठिन तथा स्कूलों की वास्तविकता से दूर हैं। उसने अध्यापक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए काफी सिफारिशें की हैं। उनको भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को भेज दिया गया था। विज्ञान अध्यापकों के प्रशिक्षण में सुधार के लिए, भारत सरकार द्वारा, अध्यापक प्रशिक्षण में सुधार के लिए, भारत सरकार द्वारा, अध्यापक प्रशिक्षण स्कूलों और कालेजों के, उपस्कर मुहैया करने की एक योजना शुरू की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भी अध्यापक कालेजों को सहायता देने की एक योजना है।
- 3. इन प्रयत्नों के बावजूद, अधिकांश अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं के पास, आधुनिक उपस्कर, प्रयोगशालाएं पुस्तकालय तथा भवन जैसी भौतिक सुविधाओं की कमी है। अनेक संस्थाएं, प्राईवेट प्रबन्धकों के अधीन हैं और जनके पास न्यूनतम सुविधाओं की भी व्यवस्था करने के लिए

वित्तीय साधन नहीं हैं। इस समय देश में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए 1342 अध्यापक प्रशिक्षण स्कूल और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए 351 कालेज हैं।

यह सच है कि हाल ही में प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या अधिक हो गई है। कुछ राज्य सरकारों ने अनेक अथवा सभी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को अपने-अपने राज्यों में बन्द करने का भी निर्णय किया है।

- 4. राज्यों के अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की अविधि और स्तरों में विभिन्नता के अलावा, राज्यों के बीच प्रशिक्षित अध्यापकों की प्रतिशतता में व्यापक विभिन्नता है। प्रशिक्षित अध्यापकों की प्रतिशतता 18 प्रतिशत से लेकर 99 प्रतिशत तक है। प्राथमिक अध्यापकों के अईताएं मिश्रिल स्कूल, उत्तीर्ण से लेकर, दो वर्ष के प्रशिक्षण के साथ प्रथम श्रेणी में उच्च माध्यमिक स्तर तक है।
- 5. देश में इस समय प्राथमिक शिक्षा को व्यापक आधार पर विस्तार और उच्च माध्यमिक स्तर के अन्त तक स्कूल शिक्षा में मामूली परिवर्तन हो रहा है। देश के सभी शिक्षा संबंधी प्रयत्नों के आधार के रूप में, स्कूली शिक्षा के महत्व और गैक्षिक पद्धति में स्कूलों के अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, सरकार को यह अभिमत है कि अध्यापक शिक्षा की किस्म के सुधार के लिए, सम्मिलत प्रयत्न करने चाहिए । यह महसूस किया गया है कि अध्यापक शिक्षा की योजनाओं की आयोजना और समन्वय के संबंध में सरकार को सलाह देने के लिए एक अखिल भारतीय संस्था स्थापित की जानी चाहिए । केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 18-19 सितम्बर 1972 को हुए अपने 36 वें अधिवेशन में, इस प्रस्ताय का समर्थन किया । इसलिए, सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् स्थापित करने का निर्णय किया है। परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

द् म । गम्नालाखत सदस्य हाग .—	ı
1. केन्द्रीय शिक्षा मंत्री	अध्यक्ष
2. प्रत्येक राज्य शिक्षा विभाग का एक-	
एक प्रतिनिधि	21 सदस्य
 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का 	
एक प्रतिनिधि	1 सदस्य
 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा 	
परिषद् का प्रतिनिधि	1 सदस्य
 केन्द्रीय गिक्षा सलाहकार बोर्ड 	1 सदस्य
 आयोजना आयोग का एक प्रतिनिधि 	1 सदस्य
7. राष्ट्रीय गैक्षिक अनुसंधान और	
प्रशिक्षण परिषद्का एक प्रतिनिधि	1 सदस्य
8. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक	•
अध्यापक प्रशिक्षण, माध्यमिक अध्यापक	
त्रशिक्षण, तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण	
और व्यावसायिक अध्यापक प्रशिक्षण	

के क्षेत्रों में बारह विशेषज्ञ-भारत

12 सदस्य

सरकार द्वारा मनोनीत

9. शिक्षा सचिव

1 सदस्य

10. परिषद् के अध्यक्ष द्वारा सदस्य-संजिव के रूप में नामजद किया जाने वाला एक व्यक्ति

1 सदस्य

कुल

41 सदस्य

6. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नामजद सदस्यों की कार्याविध मनोगयन की तारीख से तीन वर्षों के लिए होगी । मनोनीत व्यक्ति के त्यागपन्न, मृत्यु इत्यादि के कारण यदि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् में कोई रिक्ति होती है तो इस रिक्त स्थान को तीन वर्षों की कार्याविध के बकाया काल के लिए एक नए मनोनीत व्यक्ति से भरा जा सकता है।

- 7. परिषद् के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :--
 - अध्यापक शिक्षा सहित पूर्व-सेवा और सेवा कालीन प्रशिक्षण, अध्यापक शिक्षा की पाठ्यचर्या के मूल्यांकन और पाठ्यचर्या के संशोधन करने में हुई प्रगित के आवधिक पुनरीक्षण से सम्बन्धित।
 - 2. सभी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना;
 - [3. राज्य सरकारों के, उनके द्वारा परिषद् को भेजे गए किसी भी मामले पर सलाह देना;
 - अध्यापक जिक्षा ते संबंधित थोजनागत योजनाओं, दोनों केन्द्रीय और राज्य, की प्रगति की पुनरीक्षण करना;
 - अध्यापन तिक्षा में पर्याप्त स्तरों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को सलाह देना;
 - भारत सरकार द्वारा परिषद् को सौपा गया कोई अन्य मामला।
- श्रिक्द के अपनी इच्छानुसार उप समितियों और
 श्रीक्षक समितियों नियुक्त करने के अधिकार होंगे।
- 9. सरकार को, किसी भी समय जैसा आवश्यक समझा जाए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को पुनर्गठित करने के अधिकार होंगे।
- 10. परिषद् के अध्यक्ष को, परिषद् की किसी भी बैठक अथवा उसकी किसी समिति में भाग लेने के लिए विशेष प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने का अधिकार होगा।
- 11. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा, परिषद् को शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय से सम्बद्ध किया जाएगा, जोिक परिषद् से सम्बन्धित सारे कार्य की देखभात करेगा।

आवेश

12. यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि राष्ट्रीय सिनवालय/मंत्नालयों/शारत सरकार के विभागों/सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सभी विश्वविद्यालयों/राष्ट्रीय मैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्/सभी अध्यापक संघों/संगठनों इत्यादि और अन्य सभी सम्बन्धित को भेज दी जाए ।

13. यह भी आवेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्न में प्रकाशित किया जाए ।

टी**॰** आर॰ जयरामन संयुक्त सचिव

समाज कल्याण विमाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 11 मई 1973

शुद्धिपस

सं॰ 13/11/72-एस० डब्ल्यू-5—इस विभाग के सम संख्यक संकल्प दिनांक 23 जून, 1972 तथा मुद्धि-पन्न, विनांक 23 जनवरी, 1973 एवं 7 मार्च, 1973 के प्रति-स्थापन में पुनर्गठित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की रचना निम्नलिखित प्रकार से होगी:—

- 1. समाज कल्याण विभाग (शिक्षा और अध्यक्ष समाज कल्याण मंत्रालय) में उप मंत्री
- 2. श्री पी० एन० लूथरा, सदस्य अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग भारत सरकार, नई दिल्ली।
- उप सचिव (जेल कार्य से संबद्ध) सदस्य गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
- निवेशक, सदस्य पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
- 5. श्री ए० के० श्रीनिवासमूर्ति, सदस्य उप विधायी परामर्श दाता, विधि मंत्रालय, नई दिल्लो।
- 6. श्री जे० जे० पानाकल, सदस्य अपराध विज्ञान तथा सुधार प्रशासन विभाग के प्रधान, टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसिस, बम्बई ।
- 7. श्री सुशील चंद्र, सदस्य निदेशक, समाज कल्याण तथा मानव सम्बन्धों का जे० के० संस्थान, लखनऊ, विश्वविद्यालय, उ०प्र०।

सदस्य

- प्रोफेसर (डा०) सीता बसु, सुधार सेवाओं तथा सामाजिक कार्य में ज्येष्ठ लेक्चरार, स्कूल आफ सोशल वर्क, 3, युनिवर्सिटी रोट, नई दिल्ली-7
- जेलों के महानिरीक्षक, सदस्य महराष्ट्र, बम्बई ।

10. जेलों के महानिरीक्षक	सदस्य
पश्चिम बंगास, कलकत्ता ।	
11. जेलों के महानिरीक्षक,	सदस्य
तमिल नाडु, मद्रास ।	
12. जेलों के महानिरीक्षक,	सदस्य
उत्तर प्रवेश, लखनऊ ।	
13. जेलों के महानिरी क्ष क,	सदस्य
पंजाब, चंडीगढ़ ।	
14. जेलों के महानिरीक्षक,	सदस्य
केरल त्रिवेन्द्रम ।	
15. समाज कल्याण निदेशक	सदस्य
महाराष्ट्र, पूना ।	
16. समाज सुरक्षा निदेशक	सदस्य
गुजरात, अहमदाबाद ।	
17. समाज कल्याण निवेशक,	सदस्य
मध्य प्रदेश, भोपाल ।	
18. निदेशक,	सदस्य-सन्तिव
सुधार सेवाओं का केन्द्रीय ब्यरो	
समाज कल्याण विभाग	
भारत सरकार,	
नई दिल्ली ।	

आदेश: ----आदेश दिया जाता है कि इस शुद्धि पत की प्रतिलिपि बोर्ड के सभी सदस्यों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों योजना आयोग, मंत्रीमंडल राजिवालय प्रधान मंत्री राचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसद कार्य विभाग, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के सभी मुख्य सचिवों को प्रेषित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस णुद्धि पल्ल को साधारण सूचना के लिए भारत सरकार के राज पत्न में प्रकाशित किया जाए ।

टी० एस० एन० स्वामी, अबर सचिव

मौबहुन एवं परिषहन मंद्रालय

नई निल्ली, विनांक 4 मई, 1973 संकल्प

सं० 7-एम० डब्ल्यू० सी०(1)/73-एम० ए०—-परिवहन तथा संचार मंत्रालय परिवहन विभाग के संकल्प सं० 55-एम० ए० (6)/56-1, दिनांक 28 जनवरी, 1958, 55-एम० ए० (16)/57-1, दिनांक 31 जुलाई, 1958, 55-एम० ए० (34)/59-1, दिनांक 29 दिसम्बर 1960, 55-एम० ए० (34)/59-III दिनांक 10 फरवरी, 1961, 55-एम० ए० (57)/58, दिनांक 1 नवम्बर, 1961, 55-एम० ए० (27)/62-1, दिनांक 19 अगस्त, 1963, 55-एम० ए० (9) / 105, दिनांक 25 मई 1966, तथा 55-एम० ए० (4)/67, दिनांक 12 फरवरी, 1969 के साथ पठित भारत सरकार के भूत पूर्व परिवहन मंत्रालय के संकल्प सं० 55-एम० ए० (5)/52, दिनांक 8 मई, 1954

के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार इस संकल्प की से तारीख 2 वर्षों की और अवधि के लिए निम्नलिखित सदस्यों की इक यात्री कल्याण समिति नियुक्त करती हैं।

डैक याली कल्या**ण** समिति बम्बई

- 1 प्रधान अधिकारी जल परिवहन विभाग, अध्यक्ष बम्बई ।
- 2. उत्प्रवासी संरक्षक, बम्बई । सदस्य
- 3. उपायुक्त शुलिस, बम्बई ।
- 4. प्रबन्धक, बम्बई पत्तन व्यास डाकस, बम्बई । ,,
- 5. पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी, अम्बई ।
- सीमा शुल्क कलैक्टर, निवारक विभाग, बम्बई ।
- मुख्य पत्तन अधिकारी तथा महाराष्ट्र सरकार के उप सचिव भवन तथा संचार विभाग, बम्बई।

गैर-सरकारी सदस्य

- श्री एस० के० कादर, सदस्य, लोक राभा।
- श्री आर० बी० बैलोस, सदस्य विधान सभा, दापोली, जिला रतनगिरी ।
- 10. श्री एच० एम० दलवाई, सदस्य विधान सभा, ब्लाक सी, ग्राउन्ड फ्लोर एक्सप्रेस, कोर्ट, चर्चगेट, बम्बई-1
- श्रीमती विजय वैनगानकर, आनरेरी मैजिस्ट्रेट, मलवान ।
- 12. श्री जे० एल० डान्डेकर, जे०पी० जनजीरा, मुख, जिला कोलवा।
- श्री विचायक, सेठ भा दूसकर, श्रीवर्धन, जिला कोलवा ।
- 14. श्री के० पी० शाह, एम० एल० ए०, स्टेशन रोड, जाम नगर।
- श्री प्रताप भाह, एम० एल० ए०, 1874, ऋष्णा नगर, भावनगर-2 ।
- 16. श्री एस० एम० याह्या, एम० एल० ए० दिलशाद मन्जिल, नवाया कालोनी, पोस्ट मतकल, उत्तरी कनारा,
- 17. श्री घनग्याम दास पोद्दार, मैंसर्स नाथुराम नारायण (प्रा०) लि० रुस्तम बिल्डिंग, 29, चर्च गेट, स्ट्रीट, यम्बई 1

आवेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति राष्ट्रपित के निजी एवं सैनिक सचिव, प्रधान मन्त्री सचिवालय, लोक सभा सचि- वालय, (10 प्रतियों सिहत जिनमें 5 प्रतियां सिमित शाखा के लिए है) मन्त्रीमन्छल सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मन्त्रालय, सभी राज्य सरकार, कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के अध्यक्ष, कलकत्ता, अध्यक्ष बम्बई पत्तन व्यास, बम्बई, अध्यक्ष मद्रास पत्तन व्यास मद्रास, इंडियन नैशनल, स्टीमणिप ओनरस एसोशियेशन, सिन्धिया हाउस, ब्लार्ड एस्टेट, बम्बई, नौवहन महानिदेशक, जहाज भवन, फोर्ट स्ट्रीट, बम्बई-1, (100 फालतू प्रतियों सिहत) जो भारत में नौवहन कम्पनियों में वितरण के लिए हैं, सदस्य, राष्ट्रीय हारबर बोर्ड तथा राष्ट्रीय नौवहन बौर्ड प्रधान अधिकारी जलपरिवहन विभाग, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास कलकत्ता में डैंक यात्री कल्याण सिमित के अध्यक्ष एवं सदस्य को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

> एन० आर० रे**डडी**, संयुक्त स**चिय**

सिचाई और विद्युस् मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 मई 1973

संकल्प

सं० 17/37/73-भा० एवं व्यास — पाँग बांघ और आनुषंगिक कार्यों के निर्माण के कार्यक्रम का अध्ययन करने और इस बात को ध्यान में रखते हुए आगामी रखी की ऋतु में उपयोग हेतु पाँग बांघ जलाशय में जल का संचय करने के विचार से पैनस्टाक सुरंग 'पी' और 'पी2' में बहाब को बन्द करने के लिए उचित समय और बांघ की सुरक्षा को सुनिष्चित करने के बारे में सलाह देने के लिए भारत सरकार ने एक समिति स्थापित करने का निर्णय किया है। इस समिति में निम्नलिखित इंजीनियर होंगे: —

- 1 श्री मोती राम, आई० एस० ई० (सेवा-निवृत्त) अध्यक्ष
- 2. श्री हरिसिंह, चौधरी सदस्य
- 3. श्री वाई० के० मूर्ति सदस्य

यह समिति कार्यस्थलों का दौरा करेंगी और 10 दिन के अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

आवेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति, (1) श्री मोती राम, आई० एस० ई० (सेवा-निवृत्त), (2) श्री हरिसिंह चौधरी और (3) श्री वाई० के० मूर्ति को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपक्ष में प्रकाशित कर दिया जाए ।

बी० एस० बंसल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई, 1973

संकल्प

सं० 14/6/72- बब्ल्यू० डी० जिल्द-दो—इस मंत्रालय की संकल्प सं० 14/6/72- डब्ल्यू० डी०, दिनांक 12 जून, 1972 हारा किवेरी जल, विभिन्न समयों पर उसका समुपयोजन, सिंचाई पद्धतियों और कावेरी वेसिन में मौजूदा निर्माण-धीन और प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में सभी संबंधित आंकड़े इकट्ठे करने के लिए एक तथ्यान्वेषी समितति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 15 दिसम्बर, 1972 को भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी है। 29 अप्रैल 1973 को नई दिल्ली में हुई एक बैठक में केरल, मैसूर और तिमलनाडु के मुख्य मंत्रियों ने इस रिपोर्ट पर विचार किया। मुख्य मंत्रियों ने इच्छा व्यक्त की कि समिति से, ऐसे सस्यापनों के उपरान्त, जिन्हें वे आवश्यक समझें, स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाए।

- 2. अतः भारत सरकार ने तथ्यान्वेषी समिति की 3 महीने की अवधि के लिए पुनः क्रियाशील करने का निर्णय लिया है, जिसमें निम्नलिखित तीन सदस्य होंगे:——
 - 1. श्री न्यायमूर्ति बी० डी० बाल बम्बई उच्च न्यायालय के सेघा निवृत्त न्यायाधीश ।
 - 2. श्री पी० आर० अहुआ सेवा निवृत्त आयक्त (सिंघु) एवं संयुक्त सचिव, सिंचाई और विद्युत मंत्रालय।
 - 3. श्री जे० एस० पटेल सेवा निवृत्त, कृषि आयुक्त, खाद्य और कृषि मंत्रालय।

यह समिति फसली क्षेत्र, सिचित शुद्ध क्षेत्र, सिचित फसली क्षेत्र और भिन्न-भिन्न समय पर जल समुपयोजन संबंधी अन्य आंकड़ों के बारे में राज्य सरकारों द्वारा इसे पहले भेजी गई सूचना का पुनरवलोकन करेगी तथा राज्य सरकारों के पास जपलब्ध अन्य आंकड़ों विशेषकर प्रकाशित आंकड़ों, के साथ ऐसे सत्यापन करेगी, जो कि आंबश्यक हों।

यह समिति 15 मई, 1973 से अपना कार्य प्रारम्भ कर देगी तथा भारत सरकार, सिचाई और विश्वतमंत्रालय को अपनी रिपोर्ट 14 अगस्त, 1973 तक प्रस्तुत करेगी।

आवेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति तमिलनाडु मैं-तूर और केरल की सरकारों राष्ट्रपति के सचिवालय , प्रधान मंत्री सचिवलाय योजना आयोग और वित्त मंत्रालय को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत सके राज पत्र में प्रकाशित किया जाए ।

रा० वा० स्वाह्यण्यम, सचिय

निर्मीण और आबास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 मई 1973

संकल्प

विषय: -केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यप्रभारित कर्मचारियों का उनकी कुशसता के अनुसार वर्गीकरण।

सं० 11015 (46)/72-ई० डब्ल्य०4--भारत सरकार ने ''केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों का उनकी कुपलता के अनुसार वर्गीकरण करने की समिति 1973'' नामक एक समिति गठित करने का निर्णय किया है।

- 2 समिति का गठन इस प्रकार से होगा :---
- (i) श्री जे**० डी० ख**न्ना, उप-सचिव संयोजक (निर्माण) निर्माण और आवास मंत्रालय
- (ii) श्री मेहर सिंह, सदस्य अवर सचिव, वित्त मंत्रालय (डबुल्यू० और ई०)
- (iii) श्री पी० एस० मजुमदार, सदस्य अधीक्षक इन्जीनियर, दिल्ली केन्द्रीय परिमण्डल संख्या III, नई दिल्ली।
- (iv) श्री जी० के० खेमानी, सदस्य अधीक्षक इन्जीनियर, दिल्ली केन्द्रीय विशुत परिमण्डल संख्या III, नई दिल्ली।
- (v) सरकार द्वारा मनोनीत सैनिक सदस्य इंजीनियरी सेवा का एक प्रतिनिधि

श्री एम० पी० मखीजानी, श्रम-अधिकारी, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

3 विचारणीय विषय:---

समिति के निम्नलिखित विचारणीय विषय होंगे:--

(i) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की कार्य-प्रभारित स्थापना के अकुशल, अर्द्ध कुशल, कुशल और अत्यस्त कुणल पदों के प्रस्थेक पद के कार्य-मार और उत्तरदायित्व को उनको सौंपे गए कार्य की जटिलताओं को, कार्य करने के लिए अपेक्षित कुशलता को, कार्य में लाये गए औजारों और उसमें आई प्रक्रियाओं को देखते हुए वर्तमान वर्गीकरण का पुनरीक्षण करना और जहां कहीं आवश्यक हो, उनके लिए उपयुक्त संशोधित वर्गीकरण का सुझाव देना, जिससे कि तीसरे वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर निर्धारित गए वेतनमानों में वर्करों को उपयुक्त रूप से आसन किया जा सके।

- (ii) अस्य विभागों में इस प्रकार के पदों के लिए अपनाए गए वर्गीकरण के प्रकाश में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की कार्य-प्रभारित स्थापना के पदों के वर्गीकरण में असंगतियों की यदि कोई हो, जांच करना तथा अन्य सभी सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसी असंगतियों को दूर करने के उपायों का सुझाल देना।
- 4. समिति अपना कार्य पूरा करके 31 अगस्त 1973 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी।
- 5. समिति अपने कार्य तथा प्रक्रिया संबंधी अन्य मामलों के लिए पद्धति निर्धारित करने में स्वतन्त्र होगी।

आरोग

(1) आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाए यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत में प्रकाशित किया जाए ।

पीं वे ने सेन, संयुक्त सचिव

भम और पुनवांस मंत्रालय (पुनवांस विभाग)

नई दिल्ली-11, दिनांक 24 अप्रैल 1973

संकल्प

सं० 18(22)/72-पुन०-II---भारत सरकार के पुनर्वास मंत्रालय के संकल्प संख्या 29(13)/64-आर० आर० /पुन०-II दिनांक 25 नवम्बर 1965 तथा भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय, पुनर्वास विभाग के संकल्प संख्या 11(8)/66-पुन०-II, दिनांक 16 जनवरी 1968 तथा श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, पुनर्वास विभाग के संकल्प संख्या 3(51)/71-पुन०-III, दिनांक 4 अगस्त, 1971 की गर्तों के अनुसार गठित निदेशन समिति में श्रीध० छुष्ण अध्यर संयुक्त सचिव, के स्थान पर श्री एच० एम० बुटालिया, संयुक्त सचिव, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, पुनर्वास विभाग को तत्काल प्रभाव से सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है।

आबेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति निम्नलिखित को भेज दी जाए:

- 1. समिति के सभी सदस्य ।
- भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
- अयोजना आयोग, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय के निजी और सैनिक सचिव।
- 4. राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों के मुख्य सचिव।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति आम जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपक्ष में प्रकाशित कर दी जाए।

बी० एम० घोष, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 22nd May 1973

/No. 34-Pres./73.—The President is pleased to direct that the following amendments shall be made in the Statutes relating to the Poice (Special Duty) Medal published in Part I, Section 1, of the Gazette of India of the 3rd March, 1962, under Notification No. 29-Pres./62, dated the 23rd February, 1962 namely :-

- (1) In the preamble to the Statutes for the words "members of the Police Forces including the Central Reserve Police and the Central Intelligence Bureau" substitute the following:-
 - "members of the Police forces, Central Police/ Security Organisations".
- (2) For Clause Thirdly substitute the following:—
 - The medal shall be awarded to those members of the Police forces, Central Police/Security Organisations who have performed service in such conditions and for such periods as may be recognised from time to time by the Government of india for the purposes of this award. Awards may be made posthumously.
- (3) For Clause Sixthly substitute the following:—

The names of those to whom this medal may be awarded may be published in the Gazette of India and a Register of such names may be kept in the Ministry of Home Affairs by such person as the President may direct.

No. 35-Pres/13.—The President is pleased to direct that the following amendment shall be made in the Rules relating to the Polico (Special Duty) Medal published in Part I, Section 1 of the Gazette of India of 3rd March, 1962, under Notification No. 30-Pres./62. dated the 23rd February, 1962:-

"Rule 2 may be deleted."

A. MITRA, Secy. to the President

are all properties to the second of the sec LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-1, the 14th May 1973

No. 1(2)-PU/73.—The following Members of Lok Sabha and Rajya Sabia have been declared as duly elected to serve as members of the Committee on Public Undertakings for the term ending on the 30th April, 1974 :-

Members of Lok Sabha

- 1. Shri Diuen Bhattacharya
- 2. Shri T. H. Gavit 3. Shri K. Gopal
- 4. Shri J. Matha Gowder 5. Shrimati Subhadra Joshi
- 6. Dr. Mahipatray Mehta
- 7. Dr. Sankta Prasud 8. Shri Nawal Kishore Sharma 9. Shri Ramavatar Shastri 10. Shri R. P. Yadav

Members of Rajya Sabha

- 1. Shri M. S. Abdul Khader 2. Shri Lal K. Advani
- 3. Shri U. N. Mahida
- 4. Shrimati Purabi Mukhopadhyay
- Shri Suraj Prasad

The Speaker has been pleased to appoint Shrimati Subhadra Joshi as Chairman of the Committee.

M. A. SOUNDARARAJAN, Dy. Secv.

New Delhi-1, the 14th May 1973

No. 5/1/73/PAC.—The following Members of Lok Sabha and Rajya Sabha have been elected to serve as Members of the Committee on Public Accounts for the term ending on 30th April. 1974-

Members of Lok Sabha

- Shri Dharamrao Sharanappa Afzalpurkar
 Shri Virendra Agarwala
 Shri S. C. Besta

- 4. Shri Jyotirmov Bosu
- 5. Shri M. Deiveckan
- 6. Shri C. D. Gautam 7. Shri Y. S. Mahajan
- 8 Shri Bibhuti Mishra
- 9. Shri H. N. Mukerjee
- 16. Shri Paripoornanand Painuli11. Shri Narain Chand Parashar

- 12. Shri H. M. Patel 13. Shri P. Antony Reddi 14. Shri Biswanarayan Shastri 15. Shri Sunder Lal

Members of Rajya Sabha

- 16. Shri M. Anandam
- 17. Shri Golap Barbora18. Shri Bipinpal Das

- 19. Shri Nawal Kishore 20. Shri P. S. Patil 21. Shri Sasankasekhar Sanyal
- 22. Shri Sawaisingh Sisodia
- 2. The Speaker has been pleased to appoint Shri Jyotirmoy Bosu as the Chairman of the Committee,

M. S. SUNDARESAN, Dy. Sc.y-

New Delhi-1, the 14th May 1973

No. 3/1/ECI/73 —The Speaker has been pleased to appoint Shri Kamal Nath Towari as Chairman of the Compleased to mittee on Estimates for the term ending on the 30th April. 1974

G. D. SHARMA, Dy. Secy.

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi-1, the 14th May 1973

CORRIGENDUM

No. 15/2/72-ASI(1)—In the Department of Personnel Corrigendum No. 15/2/72-AIS(I)(published in Part I Section I of the Gazette of India dated the 11th November, 1972) to the Notification of even number dated the 3rd June, 1972, published in Part I Section 1 of the Gezette of India dated the 3rd June, 1972, the following changes may be effected:-

Sl. Reference in No. Gazette

For

1. Page 1133, Col. 1. under reforence, against Page 548, Col. 1, item (c) of para 9, line 1 onwards.

For the words Officers 'Sioned who were commissioned after Ist November, read the words (c) An Emergency Commissioned/ Service Short Commissioned Officers who were commissioned after the 1st November.

For the Officers 'sioned who were commissioned after Tst November. 1962 but before the 10th January, 1968, or who had joined any precommission training before the latter date, but who were Commissioned after that date' read the words (c) An Emergency Commissioned Short Service Commissioned Officer who was commissioned after the Ist November, 1962, but before the 10th January, 1968, or who had joined any pre-commission training before date the latter but who was comafter missioned that date.'

2. Page 1133, Col. 1, Page 548, Col. 1. Page 548, Col. 1, under reference, under item (c) lines Note 1, under item lines 8-9. 2 and 3.

(c) lines 2-3.

3. Page 1133, Col. 1, For the word 'for- For the 'forwad' under Reference, ward' read the word against Page 548, word 'forward' 'forward'.

Col. 2, para 12, line 3.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department) (Journal Wing)

New Delhi, the 16th May 1973 AMENDMENT TO RESOLUTION

No. E-13016/3/72-JL(HLB).—In the Resolution of the Ministry of Law & Justice No. 22/4/69-JL(Admn) dated the 1st March, 1972, relating to the composition of the Evaluation Committee for rendering advice for the effective implementation of the scheme for writing, translation and publication of standard law books in Hindl, for Serial number 4 and entries against such serial number, the following shall be substituted, namely:—

"4 Shri S. N. Chaturvedi, Member, Official Language (Legislative) Commission, New Delhi—Member."

N. K. SETH, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 15th May 1973

RESOLUTION

No. E. 13011/2/73-Hindl-2,—The Government of India have been pleased to appoint Shri Uma Shankar Dikshit, Minister of Home Affairs as Chairman of the Hindi Salahkar Samiti reconstituted under this Ministry's Resolution No. 8/6/71-Hindi-2, dated 9th August 1972 in place of Shrimati Indira Gandhi, Prime Minister.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments, Administrators of Union Territories, all the Ministries and Departments of the Government of India, President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General, Accountant General, Central Revenues, New Delhi, the Lok Sabha Secretariat and the Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. N. DHIR, Dy. Secy.

New Delhi-110001, the 16th May 1973

No. 26/12/72-ANL.—In partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. 26/12/72-ANL dated the 4th October, 1972, the President is pleased to direct that in paragraph 3 of the said notification, the following proviso shall be inserted:—

"Provided that the term of membership of such members elected to the first Advisory Committee constituted under this notification shall be upto the 31st of March, 1974"

JAYAKER JOHNSON, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 19th May 1973

No. 1(3)/73-FPZ.—The President is pleased to appoint Shri S. Rajgopal, IAS as Development Commissioner. Santa Cruz Electronics Export Processing Zone, Bombay with effect from the forenoon of 1st May, 1973, until further orders.

N. S. VAIDYANATHAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel) PUBLIC NOTICE

Subject:—Introduction of I.S.I.—Certification Marks Scheme for Steel.

New Delhi, the

1973

No. SC(1)-32(4)/72.—In partial modification of paras 2 and 10 of this Ministry's public Notice No. SC(C)-2(44)/63-II dated the 4th January, 1965, it has now been decided that, in view of the progress made in the processing of steel and with the gradual enlarging of the ISI Quality Marking Scheme to cover a large number of specifications, certifications and testing of all steels covering the non-ISI specifications will henceforth be covered by mutual agreement between the producers and consumers since it is the intention of the Government to reduce the non-ISI specifications to the minimum in due course. However, test certificates will continue to be issued by DI (Met) as the authorised agency/authority, if any consumer wishes to have a test certificate issued by a third party, that is, the DI (Met).

T. GHOSH, Iron and Steel Controller

DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY

New Delhi-29, the 11th May 1973

No. DST-9/1(2)/73-NHM.—The President is pleased to appoint Shri Iftikhar Alam Khan. Lecturer-cum-Curator in the General Education Centre, Aligarh Muslim University, Aligarh as Curator in the Natural History Museum, Department of Science & Technology in the scale of Rs. 700—40—1100—50/2—1250 in a temporary capacity for one year w.e.f. 7th May, 1973 (F.N.).

M. R. RAJAGOPALAN, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE (Department of Agriculture)

New Delhi, the 14th May 1973

No. 2-8/73-FFHC.—In partial supersession of the Govt. of India Resolution No. 2-6/70-FFHC dated the 20th March. 1971 and dated the 25th May,/16th June, 1972 and in terms of rule 29 of the Memorandum of Association and Rules & Regulations of the Indian Freedom From Hunger Campaign Society, New Delhi the Govt. of India have decided to reconstitute the Governing Council of the Indian Freedom From Hunger Campaign Society with immediate effect till further orders as under:—

Chairman

- 1. Minister of State in the Ministry of Agriculture. Vice-Chairman
- 2. Secretary, Department of Agriculture.

 Member Secretary
- 3. Deputy Commissioner, FFHC, Deptt. of Agriculture.

 Members
- Λ Representative of the National Tonnage Club of Farmers in India.
- 5. A Representative of the Bharat Krishak Samaj.
- A Representative of the Association of Voluntary Agencies for Rural Development.
- A Representative of Action for Food Production (AFPRO).

Assistant Secretary

- 8. Assistant Commissioner, FFHC, Deptt. of Agriculture.

 Special Invitee
- A Representative of Food & Agricultural Organisation of the United Nations,

ORDER

Ordered that a copy of the Notification may be communicated to all State Governments, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Department of Parliamentary Affairs. The Private and Military Secretaries to the President, The Cabinet Secretariat, the Prime Minister's Secretariat, the Vice-President's Secretariat, all Ministries of the Govt. of India, Planning Commission, the Auditor General of India, all members of the Indian FFHC Society and all Organisations connected with the FFHC.

Ordered also that the notification be published in the Gazette of India.

TRIBENI PRASAD SINGH, Secy.

New Delhi-110001, the 19th May 1973

No. 10-1/73-FAIT.—With reference to Notification No. 10-2/71-FAIT dated the 16th/20th October, 1971. Shri Mohan Singh, Member of Legislative Assembly, Uttar Pradesh, resident of village Tuloi, District Kai-Bareli, has been nominated on the National Food and Agriculture Organisation Liaison Committee reconstituted under Resolution No. 10-1/65-FAIT dated the 9th September. 1966, as amended to date, to serve on this Committee as representative of Rural Peoples' Interests for a period of three years with effect from the date of issue of this Notification, vice the late Shri Raj Narain Misra.

P. V. SHENOI, Director (Foreign Aid)

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 21st May 1973 RESOLUTION

Subject: Establishment of a National Council for Teacher Education.

No. F 7-6/71-Schools 2.—The Education Commission of 1964-66 had discussed the role of the Government of India in the maintenance of standards in teacher education. The Commission recommended the provision of liberal funds for improving teacher education. It also suggested that University Grants Commission should, in collaboration with the National Council of Education Research and Training at the Liberatory Research and Research an Council of Education Research and Training, establish a Joint Standing Committee for Teacher Education. Such a committee has been established.

- 2. The Education Commission also recommended that both at the primary and secondary stages a minimum of two years at the primary and secondary stages a minimum of two years training should be provided to the teachers. The Commission had observed that the existing programmes of teacher education were largely traditional, rigid and divorced from the realities of schools. It made a number of recommendations for re-organizing teacher education. These were commended by the Government of India to the State Governments. With a view to improving the training of science teachers. Government of India launched a scheme to supply equipment to teacher training schools and colleges. The University Grants Commission has a scheme to assist teachers' colleges.
- 3. Despite these efforts, most of the teacher training institutions lack physical facilities such as modern equipment, laboratories, libraries and buildings. Many institutions are under private management and lack financial resources to provide even the minimum facilities. There are now in the country 1342 teacher training schools for primary school teachers and 351 colleges for secondary school teachers.

There has been of late the phenomenon of over supply of trained teachers. Some State Governments had even decided to close down many or all teacher training institutions in the State concerned.

- 4. There are wide variations in the percentage of trained teachers among States, apart from variations in duration and standards of teacher training courses, The percentage of trained teachers varies from 18% to 99%. The qualification for primary teachers varies from "middle school pass" to "first class in higher secondary with 2 years training."
- 5. The country is now on the eve of a large-scale expansion in primary education and a radical transformation in school education upto the end of higher secondary stage. In view of the importance of school education as the foundation for all educational efforts in the country and the crucial role of the school teacher in the educational system, Government feel that a concerted effort should be made to improve the quality of teacher education. It is felt that an All-India body should be established to advise Government in the planning and coordination of schemes of teacher education. The Central Advisory Board of Education at its 36th session held on September, 18-19, 1972, has endorsed the proposal. Government have, therefore, decided to establish a National Council for Teacher Education. The Council will have the following members: bers :-

(i) Union Mir	nister for Education	President
(ii) One represe Department	entative from each State at of Education	21 members
(iii) A represe Grants Cor	entative of University mmission	1 member
(iv) A represent Council for	ntative of the All India r Technical Education	1 member

- (v) A representative of the Central Advisory Board of Education. 1 member (vi) A representative of the Planning Commission. 1 member (vii) A representative of the National Council of Education Research and Training. 1 member (viii) Twelve experts in the fields of pre-primary education, primary teacher training, secondary teacher training, technical teacher training and vocational teacher training nominated by the Government of India.
- (ix) Education Secretary (x) One person to be nominated by the President of the Council as Member-Secretary.

1 member 41 members

12 members

1 member

6. The tenure of the nominated members of the National Council for Teacher Education shall be three years from the date of nomination. If a vacancy arises on the National Council for Teacher Education due to resignation, death etc. of a nominated member, the vacancy may be filled for the remain-ing portion of the tenure of three years by a fresh nomination.

Total:

- 7. The terms of reference of the Council will be as fol-
 - (i) To advise Government of India on all matters concerning teacher education, including pre-service and in-service training, evaluation of curricula for teacher education and periodical review of progress in revising curricula;
 - (ii) To advise State Governments on any matter referred to the Council by them.
 - (iii) To review the progress of plan schemes, both Central and State, concerning teacher education;
 - (iv) To advise Government on ensuring adequate standards in teacher education;
 - (v) Any other matter entrusted to the Council by the Government of India.
- 8. The Council shall have powers to appoint sub-committees and academic committees of its own.
- 9. Government shall have powers to reconstitute the National Council for Teacher Education at any time as may be considered necessary.
- 10. The President of the Council will have the power to invite special representatives to attend any of the meetings of the Council or any of its committees.
- 11. The National Council for Teacher Education will be attached to the Ministry of Education and Social Welfare which will attend to all work relating to the Council.

ORDER

- 12. Ordered that a copy of this resolution be communicated to the President's Secretariat/Ministries/Departments of the Government of India/All State Governments/Union Territories Administration/University Grants Commission/All Universities/National Council of Education Research and Training/ Teachers Associations/Federations etc. and all others conceived concerned.
- 13. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

T. R. JAYARAMAN, Jt. Secy.

(Department of Social Welfare)

New Delhi-1, the 11th May 1973 **CORRIGENDUM**

F. No. 13-11/72-SW-5.—In supersession of this Dept. Resolution of even number, dated the 23rd June, 1972 and Corrigendum dated the 23rd January, 1973 and 7th March, 1973,

on Correctional Services will be as follows:--

1. Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Ministry of Education and Social Welfare).

- 2. Shri P. N. Luthra, Additional Secretary, Department of Social Welfare, Government of India, New Delhi.
- 3. Deputy Secretary, (dealing with Jail Affairs) Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.
 - 4. Director, Bureau of Police Research and Development Ministry of Home Affairs, New Delhi.
 - Srinivasamurthy. Legislative Counsel, Ministry of Law, New Delhi.
 - Shri J. J. Panakal, Head of the Department of Crimi-nology and Correctional Administration, Tata Institute of Social Sciences, Bombay.
 - Shri Sushil Chandra, Director of J. K. Institute of Sociology and Human Relations, University of Lucknow. Lucknow, Uttar Pradesh.
 - Prof. (Dr.) Sita Basu, Senior Lecturer in Correctional Services. and Social Work, Delhi School of Social Work, 3, University Road, Delhi-7.
- 9. Inspector General of Prisons. Maharashtra, Bombay.
- 10. Inspector General of Prisons, West Bengal, Calcutta.
- 11. Inspector General of Prisons, Tamil Nadu, Madras.
- 12. Inspector General of Prisons Uttar Pradesh, Lucknow,
- 13. Inspector General of Prisons. Punjab, Chandigarh.
- 14. Inspector General of Prisons, Kerala, Trivandrum.
- 15. Director of Social Welfare, Maharashtra, Poona.
- 16. Director of Social Defence, Gujarat, Ahmedabad.
- 17. Director of Social Welfare, Madhya Pradesh, Bhopal.
- Member Secretary

18. Director, Central Bureau of Correctional Services, Department of Social Welfare. Government of India.

New Delhi

ORDER

Ordered that a copy of this Corrigendum be sent to all the Members of the Board, all Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat. Department of Parliamentary Affairs, Chief Secretaries of State Governments/Union Territories.

Ordered also that the Corrigendum be published in the Gazette of India for general information.

T. S. N. SWAMI, Under Secy.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (Transport Wing)

New Delhi, the 4th May 1973 RESOLUTION

No. 7-MWC(1)/73-MA.—In pursuance of the Resolution of the Government of India in the late Ministry of Transport No. 55-MA(5)/52, dated the 8th May, 1954, read with the Ministry of Transport and Communications, Department of Transport Resolutions No. 55-MA(6)/56-I, dated the 28th January. 1958, 55-MA(16)/57-I, dated the 31st July, 1958 55-MA(34)/59-I, dated the 29th December, 1960, 55-MA(34)/59-III, dated 10th February. 1961, 55-MA(5)/58, dated the 1st November. 1961, 55-MA(2)/62-I, dated the 19th August. 1963 55-MA(9)/65, dated the 25th May, 1966 and 55-MA(9)/67 dated 12th February. 1969, the Central Government is pleased to appoint the following members to constitute the Deck Passenger Welfare Committee at Bombay for a further No. 7-MWC(1)/73-MA.—In pursuance of the Resolution of Deck Passenger Welfare Committee at Bombay for a further period of two years from the date of this Resolution.

Deck Passenger Welfare Committee, Bombay

Chairman

1. The Principal Officer, Mercantile Marine Deptt., Bombay.

Members

- 2. The Protector of Emigrants, Bombay.
- 3. The Dy. Commissioner of Police, Bombay,

- 4. The Manager, Bombay Port Trust Docks, Bombay,
- The Port Health Officer, Bombay.
- 6. The Assit, Collector of Customs Preventive Department, Bombay,
- 7. The Chief Ports Officer and Dy. Secretary to the Government of Maharashtra, Building and Communications, Department, Bombay.

Non-Official Members

- 8. Shri S. A. Kadar, Member, Lok Sabha.
- 9. Shri R. V. Belose, M.L.A. Dapoli, Ratnagiri Distt.
- Shri H. M. Dalvai. M.L.A. Block 'C', Ground Floor, Empress Court, Churchgate, Bombay-1.
- 11. Mrs. Vijaya Waingankar, Hon. Magistrate, Malvan.
- 12. Shri J. L. Dandekar, J.P., Janjira Murud, Distt.
- 13. Shri Vinayakseth Mapuskar, Srivardhan, Distt. Kolaba.
- 14. Shri Pratap Shah, M.L.A., Station Road, Jamnagar,
- 15. Shri Pratap Shah, M.L.A., 1874. Krishna Nagar, Bhavnagar-2.
- 16. Shri S. M. Yahya, M.L.A., Dilshad Manzil, Navaya Colony, Post Bhatkal, North Kanara,
- Shri Ghanshyane Das Poddar. M/s. Nathu Ram Natain (P) Lid., Rustam Building 29, Church Gate Street, Fort, Bombay-1.
- 18. Shri Balmukand R. Agarwal, D-222, Defence Colony, New Delhi.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the Private and Military Secretaries to the President: the Prime Minister's Secretariat; the Lok Sabha Sectt. (with 10 copies including 5 copies for Committee Branch): the Cabinet Secretariat; the Planning Commission; all the Ministries of the Government of India; all State Governments; the Chairman; Commissioners for the Port of Calcutta, Calcutta; the Chairman, Bombay Port Trust, Bombay, the Chairman, Madras Port Trust, Madras; the Indian National Steam Ship Owners' Association, Scindia House, Ballard Estate, Bombay: the Association. Scindia House, Ballard Estate, Bombay: the Director General of Shipping, Jahaz Bhavan. Fort Street, Bombay-1. (with 100 spare copies) for distribution to the Shipping Companies in India. the Members of National Harbour Board and the Members of the National Shipping Board); Principal Officers Mercantile Marine Department. Bombay. Calcutta and Madras; the Chairman and Members of the Deck Passenger Welfare Committee at Calcutta, Dv. Principal Information Officer/Information Officer, P.I.B., New Delhi

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. R. REDDY, Jt. Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 10th May 1973

RESOLUTION

No. 17/37/73-B&B.—It has been decided by the Government of India to set up a Committee comprising the following Engineers to study programme of construction of Pong Dam and appurtenant works, and keeping this in view to advise the proper time for closing the flow in the penstock tunnels P1 and P2 with a view to impound water in the Pong Dam Reservoir for use in the coming rabi season and ensuring the safety of the dam:

- Shvi Moti Ram ISE (Retired)—Chairman
 Shri Hari Singh Chowdhary—Member
 Shri Y. K. Murthy—Member

The Committee will visit the sites of works and submit report within 10 days

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to (1) Shri Moti Ram. ISE (Retired), (2) Shri Hari Singh Chowdhary and (3) Shri Y. K. Murthy.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India

B. S. BANSAL, Jt. Secv.

New Delhi, the 14th May 1973

RESOLUTION

No. 14/6/72-WDVol.II.—In this Ministry's Resolution No. 14/6/72-WD, dated the 12th June, 1972 a Fact Finding Committee was appointed to collect all the connected data pertaining to Cauvery waters, its utilisation and irrigation practices as well as projects both existing, under construction and proprosed, in the basin. The Committee furnished its Report to the Government of India on 15th December, 1972. The Report was considered by the Chief Ministers of Kerala, Mysore and Tamil Nadu at a meeting held at New Delhi on 29th April, 1973. The Chief Ministers desired that the Committee should be asked to furnish clarification after such verification as is found necessary.

- 2. The Government of India have, therefore, decided to revive the Fact Finding Committee for a period of 3 months with the following three members, namely:
 - Shri Justice B. D. Bal—Retd. Judge of the Bombay High Court.
 - Shri P. R. Ahuia—Retd. Commissioner (Indus) and Joint Secretary. Min. of Irrigation and Power.
 - Dr. J. S. Patel—Retd. Agricultural Commissioner Min. of Food & Agriculture.

The Committee shall review the data supplied to it earlier by State Governments in respect of area cropped, net area irrigated, irrigated cropped area and other data relevant to water utilisation at different points of time and undertake such verification as is necessary, from other data available with the State Governments, specially those published.

The Committee will commence work with effect from 15th May, 1973 and submit its report to the Government of India in the Ministry of Irrigation & Power by 14th August, 1973.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Governments of Tamil Nadu. Mysore and Kerala, the President's Secretariat, the Prime Minister's Secretariat, the Planning Commission and the Ministry of Finance.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India.

R. V. SUBRAHMANIAN, Secy.

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING Works Division

New Delht, the 18th May 1973

RESOLUTION

SUBJECT:—Classification of the workcharged staff of the C.P.W.D. according to skills.

No. 11015(46) /72-EW4.—The Government of India have decided to set up a Committee to be known as "The Committee for categorisation of the workcharged staff of the Central Public Works Department according to skills, 1973."

2. The composition of the Committee shall be as follows:-

Convener

(i) Shri J. D. Khanna, Deputy Secretary (Works), Ministry of Works and Housing.

Members

- (ii) Shri Mehar Singh, Under Secretary, Ministry of Finance (W&E).
- (iii) Shri P. S. Majumdar, Superintending Engineer, Delhi Central Circle No. III, New Delhi.
- (iv) Shri G. K. Khemani, Superintending Engineer, Delhi Central Electrical Circle No. III, New Delhi,
- (v) A representative of the Military Engineering Service to be nominated by the Government.

Shri M. P. Makhijani, Labour Officer, Central Public Works Department, New Delhi will act as the Secretary to the Committee.

3. Terms of Reference:

The terms of reference of the Committee shall be :-

- (i) To review the existing classification of posts on the workcharged establishment of the Central Public Works Department as unskilled, semi-skilled, skilled and highly skilled, keeping in view the duties and responsibilities of each post, complexities of tasks assigned, skill required to perform jobs, tools used and processes involved in the work, and suggest appropriate revised classification, where necessary, so as to ensure proper placement of the workers into the new pay scales prescribed on the recommendations of the Third Pay Commission.
- (ii) To examine the anomalies, if any, in the classification of posts on the workcharged establishment of the Central Public Works Department in the light of the classification adopted for similar posts in other departments and suggest remedles for removal of such anomalies, keeping in view all the relevant factors,
- 4. The Committee will complete its work and submit its report to the Government by the 31st August, 1973.
- 5. The Committee will be free to lay down the method of its working and other procedural matters.

ORDER

Ordered that a copy of the resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India.

P. K. SEN, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 24th April 1973

RESOLUTION

No. 18(22)/72-RH.II.—Shri H. S. Butalia, Joint Secretary, Shram Aur Punarvas Mantralaya, Punarvas Vibhag (Department of Rehabilitation, Ministry of Labour & Rehabilitation), Government of India, has been nominated with immediate effect vice Shri D. Krishna Ayyar, Joint Secretary, as a Member of the Committee of Direction set up in terms of the Government of India, Ministry of Rehabilitation Resolution No. 29(13)/64-RR/Rehab. II, dated 25th November, 1965, read with Government of India Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation, Department of Rehabilitation's Resolution No. 11(8)/66-RH.II, dated the 16th January, 1968 and Ministry of Labour and Rehabilitation Department of Rehabilitation's Resolution No. 3(51)/71-RH.III dated the 4th August, 1971.

D. KRISHNA AYYAR, Jt. Secy.

ORDER

 O_{RDERED} that a copy of the Resolution be communicated to :—

- (i) All Members of the Committee.
- (ii) All Mantralayas/Vibhags. Bharat Sarkar.
- (iii) Jojna Ayog, Pradhan Mantri Sachivalaya, Mantri Mandal Sachivalaya and Private and Military Secretaries to the President.
- (iv) The Chief Secretaries to the State Govts./Union Territory Govts.

Ordered also that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. M. GHOSH, Under Secy.